



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (I)
PART II—Section 3—Sub-section (I)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 399]
No. 399]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 28, 1986/भाद्र 6, 1908
NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 28, 1986/BHADRA 6, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Page is given to this Part in order that it may be filed as
separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 28 अगस्त, 1986

अधिसूचना

सं. 424/86-सीमाशुल्क

सा. का. नि. 1046(अ).—केंद्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 55) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 164/86-सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 1986 को अधिकांत करने हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, अनुसंधान के प्रयोजनों के लिए अपेक्षित खपने वाले माल को, जब उसका भारत में किसी लोक-निधिक अनुसंधान संस्था द्वारा आयात किया जाए, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय समस्त सीमाशुल्क से और उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा

3 के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय समस्त अतिरिक्त शुल्क से, निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, छूट देती है :—

(1) लोक-निधिक अनुसंधान संस्था द्वारा आयातित, एक वित्तीय वर्ष में एक लाख रुपये के सकल सीआईएफ मूल्य तक के खपने वाले माल के लिए,—

(क) विज्ञान और तकनीकी विभाग या उक्त लोक-निधिक अनुसंधान संस्था से संबंधित प्रशासनिक विभाग के उप-सचिव के रैंक से अनिम्न रैंक का भारत सरकार का कोई अधिकारी प्रत्येक मामले में यह प्रमाणित करता है कि ऐसा खपने वाला माल जिसकी बाबत छूट का दावा किया गया है, ऐसा है जो लोक-निधिक अनुसंधान संस्था में अनुसंधान कार्य के लिए अपेक्षित है और संस्था किसी वाणिज्यिक क्रियाकलाप में नहीं लगी हुई है तथा वह अधिसूचना के अधीन छूट की मंजूरी के लिए सिफारिश करता है, और ऐसा प्रमाण-पत्र निकासी के समय या ऐसी अवधि के भीतर जो सहायक सीमाशुल्क कलक्टर, उचित कारण दर्शाये जाने पर, प्रत्येक मामले में अनुज्ञात करे, प्रस्तुत करता है; और

(ख) लोक-निधिक अनुसंधान संस्था का प्रधान प्रत्येक मामले में यह प्रमाणित करता है कि —

- (i) संस्था इस अधिसूचना के अर्थ में लोक-निधिक अनुसंधान संस्था है;
- (ii) ऐसा खपने वाला माल जिसकी बाबत छूट का दावा किया गया है, भारत में विनिर्मित नहीं किया जाता और ऐसा खपने वाला माल केवल अनुसंधान के प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाया जाएगा; और
- (iii) ऐसे खपने वाले माल का मूल्य जिसकी बाबत इस अधिसूचना के अधीन छूट का दावा किया गया है, जिसके अंतर्गत ऐसे खपने वाले माल का मूल्य भी है जिसकी बाबत छूट, यदि कोई है, उसी वित्तीय वर्ष में इस अधिसूचना के अधीन पहले ही ले ली गई है एक साधारण रूप से अधिक नहीं है।

(2) लोक-निधिक अनुसंधान संस्था द्वारा आयातित एक वित्तीय वर्ष के एक लाख रुपए के सकल सीआईएफ मूल्य से अधिक के खपने वाले माल के लिए,—

(क) तकनीकी विकास महानिदेशालय का औद्योगिक सलाहकार से अतिरिक्त रैंक का कोई अधिकारी प्रत्येक मामले में यह प्रमाणित करता है कि ऐसा खपने वाला माल, जिसकी बाबत इस अधिसूचना के अधीन छूट का दावा किया गया है, ऐसा है जिसका विनिर्माण भारत में नहीं किया जाता है, और ऐसा प्रमाणपत्र निकासी के समय या ऐसी अवधि के भीतर जो सहायक सीमाशुल्क कलक्टर, उचित कारण दर्शाए जाने पर प्रत्येक मामले में अनुज्ञात करे, प्रस्तुत करता है;

(ख) विज्ञान और तकनीकी विभाग या उक्त लोक-निधिक अनुसंधान संस्था से संबंधित प्रशासनिक विभाग के उप सचिव के रैंक से अतिरिक्त रैंक का भारत सरकार का कोई अधिकारी प्रत्येक मामले में यह प्रमाणित करता है कि ऐसा खपने वाला माल, जिसकी बाबत छूट का दावा किया गया है, ऐसा है, जो लोक निधिक अनुसंधान संस्था में अनुसंधान कार्य के लिए अर्पित है और संस्था किसी वाणिज्यिक क्रियाकलाप में नहीं लगी हुई है तथा वह अधिसूचना के अधीन छूट की मंजूरी के लिए सिकाटिंग करता है और ऐसा प्रमाणपत्र निकासी के समय या ऐसी अवधि के भीतर जो सहायक सीमाशुल्क कलक्टर, उचित कारण दर्शाए जाने पर प्रत्येक मामले में अनुज्ञात करे, प्रस्तुत करता है; और

(ग) लोक-निधिक अनुसंधान संस्था का प्रधान प्रत्येक मामले में यह प्रमाणित करता है कि—

- (i) संस्था इस अधिसूचना के अर्थ में लोक निधिक अनुसंधान संस्था है, और
- (ii) ऐसा खपने वाला माल, जिसकी बाबत इस अधिसूचना के अधीन छूट का दावा किया गया है केवल अनुसंधान के प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाया जाएगा।

स्पष्टीकरण—इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए “लोक-निधिक अनुसंधान संस्था” पद से ऐसी कोई अनुसंधान संस्था अभिप्रेत है जिसके पक्ष में भारतीय धन्य के पक्ष प्रमाणित से अल्पतः केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, द्वारा बहन किया जाता है।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 28th August, 1986

NOTIFICATION

NO. 424/86-CUSTOMS

G.S.R. 1046(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and in supersession of the Notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 164/86-Customs, dated the 1st March, 1986, the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts consumable goods required for the purposes of research when imported into India by any public-funded research institution, from the whole of the duty of customs leviable thereon under the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) and the whole of the additional duty leviable thereon under section 3 of the said Customs Tariff Act, subject to the conditions that :—

(1) for the consumable goods, imported by the public funded research institution, unto the aggregate CIF value of rupees one lakh in a financial year :—

(a) an officer of the Government of India not below the rank of a Deputy Secretary, in the Department of Science and Technology, or in the Ministry or Department administratively concerned with the said public funded research institution, certifies in each case that the consumable goods in respect of which the exemption is claimed are such as are required in the research activity of the public-funded research institution and the institution is not engaged in any commercial activity and recommends the grant of exemption under this Notification, and such certificate is produced at the time of clearance or within such period as the Assistant Collector of Customs may, on sufficient cause being shown, allow in each case; and

(b) the Head of the public-funded research institution certifies in each case,—

(i) that the institution is a public-funded research institution in terms of this Notification; and

(ii) that the consumable goods in respect of which exemption is claimed under this Notification are not manufactured in India and that the consumable goods would be used only for the purposes of research, and

(iii) that the value of consumable goods, in respect of which the exemption is claimed under this Notification including the value of consumable goods in respect of which the exemption, if any,

has already been availed of under this Notification in the same financial year, does not exceed rupees one lakh;

- (2) for the consumable goods, imported by the public-funded research institution, over and above the aggregate CIF value of rupee one lakh in a financial year,—

- (a) an officer of the Directorate General of Technical Development not below the rank of an Industrial Adviser certifies in each case that the consumable goods in respect of which the exemption is claimed under this Notification are such as are not manufactured in India, and such certificate is produced at the time of clearance or within such period as the Assistant Collector of Customs may, on sufficient cause being shown, allow in each case; and
- (b) an officer of the Government of India not below the rank of Deputy Secretary, in the Department of Science and Technology, or in the Ministry or Department administratively concerned with the said public-funded research institution, certifies in each case that the consumable goods in respect of which the exemption is claimed are such as are required in the research activity of the public-funded research institution and the institution is

not engaged in any commercial activity and recommends the grant of exemption under this Notification, and such certificate is produced to the time of clearance or within such period as the Assistant Collector of Customs may, on sufficient cause being shown, allow in each case; and

- (c) the Head of the public-funded research institution concerned certifies in each case,—
- (i) that the institution is a public-funded research institution in terms of this Notification; and
- (ii) that the consumable goods in respect of which exemption is claimed under this Notification would be used only for the purposes of research.

Explanation.—For the purposes of this Notification, the expression “public-funded research institution” means a research institution in the case of which not less than fifty per cent of the recurring expenditure is met by the Central Government or the Government of any State or the Administration of any Union Territory.

[F. No. 346/31/86-TRU]

K. S. VENKATAGIRI, Under Secy.

